



Economic Survey Brahmastra

आर्थिक समीक्षा राजस्थान 2025-26

अध्याय 10 — ग्रामीण विकास

Chapter 10 — Rural Development

RAS 2026 — प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा · द्विभाषी (हिन्दी + English)
संपूर्ण तथ्य · सभी डेटा टेबल · योजनाएँ · अभ्यास प्रश्न

यह सामग्री राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 पर आधारित है तथा RajStudy द्वारा परीक्षा-केंद्रित रूप में पुनर्लिखित की गई है (शब्दशः नकल नहीं)। हर तथ्य एवं आँकड़ा संरक्षित।

1 दृष्टि व राजीविका / Vision & Rajeevika

- 2047 तक राजस्थान ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी अवसंरचना, आजीविका सुरक्षा, आय-वृद्धि, जल सुरक्षा व स्वच्छता सेवाओं से 'ग्राम स्वराज' का समग्र लक्ष्य प्राप्त करेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999। By 2047, RJ achieves Gram Swaraj via empowerment, inclusive infrastructure, livelihood security, water security & sanitation. Dept of Rural Development & Panchayati Raj est. 1 Apr 1999.

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP / राजीविका)

RGAVP (Rajeevika)

- स्थापना अक्टूबर 2010 (स्वायत्त परिषद, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958); अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री; उद्देश्य — समता, वित्तीय समावेशन व आजीविका सुरक्षा; लाभार्थी चयन SECC सर्वेक्षण व सहभागिता पहचान से। Est. Oct 2010 (autonomous council, Societies Registration Act 1958); chaired by CM, vice-chair RD Minister; aims equity, financial inclusion & livelihood security; beneficiaries via SECC survey.
- NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन): जून 2011; ग्रामीण विकास मंत्रालय; संपूर्ण राज्य; केंद्र:राज्य 60:40। NRETP (राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण): विश्व बैंक सहायतित; 9 जिलों के 36 ब्लॉक; जून 2024 में समाप्त। NRLM: Jun 2011; statewide; Centre:State 60:40. NRETP: World Bank-aided; 36 blocks in 9 districts; ended Jun 2024.

2 राजीविका योजनाएं / Rajeevika Schemes

वन धन विकास योजना (Van Dhan Vikas Yojana)

विवरण

Detail: 8 जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर) में 517 वन धन विकास केंद्र
517 Van Dhan centres in 8 districts

उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (Ujala Milk Producer Co.)

विवरण

Detail: 6 जिले (कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़); 40,000 महिला डेयरी उत्पादक
6 districts; 40,000 women dairy producers

उड़ान योजना (Udaan Yojana)

विवरण

Detail: 19 दिसंबर 2021; महिला स्वच्छता-जागरूकता; सरकारी स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी पर 12 नि:शुल्क सेनेटरी पैड; नोडल महिला अधिकारिता विभाग
19 Dec 2021; 12 free sanitary pads at govt schools/colleges/anganwadis; nodal WCD

राजस्थान महिला कोष (Rajasthan Mahila Kosh)

स्थापना

Est.: 26 अगस्त 2022 (महिला समानता दिवस)

26 Aug 2022 (Women Equality Day)

ऋण

Loan: ₹40,000 तक 48 घंटे में, ₹40,000+ 15 दिन में; ब्याज 2.5% (राज्य 8% सब्सिडी); 'अपना महिला निधि' ऐप; 1,54,861 महिलाओं को ~₹735 करोड़

ऋण

₹40,000 in 48 hrs, more in 15 days; 2.5% interest (8% state subsidy); ₹735 cr to 1,54,861 women

अन्य उत्पादक कंपनियाँ व रिटेल (Other producer cos & retail)

विवरण

Detail: हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी (कोटा-बारां, सोयाबीन-धनिया); SHG उत्पादों हेतु 11 रिटेल स्टोर (जयपुर, चूरू×2, श्रीगंगानगर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, राजसमंद, कोटा)

Hadauti Women Farmer Producer Co. (Kota-Baran); 11 SHG retail stores

3 राजीविका 'सखी' व 'दीदी' मॉडल / Rajeevika 'Sakhi' & 'Didi' Model

नमो ड्रोन दीदी योजना (फ्लैगशिप) (Namo Drone Didi (flagship))

विवरण

Detail: 15 अगस्त 2023; 15,000 चयनित SHG को कृषि ड्रोन; गढ़ेपान (कोटा) से 11 मार्च 2024; ड्रोन सखी 15 दिन प्रशिक्षण + ₹1,500/माह; वित्त 80% या अधिकतम ₹8 लाख; 1,070 कृषि ड्रोन (3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान); 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित

15 Aug 2023; agri-drones to 15,000 SHGs; from Garhepan (Kota) 11 Mar 2024; Drone Sakhi 15-day training + ₹1,500/mo; 80% or max ₹8 lakh; 1,070 drones; 50 distributed in 46 blocks of 30 districts

सोलर दीदी / लखपति दीदी (Solar Didi / Lakhpati Didi)

सोलर दीदी

Solar Didi: आयु 20-45, 10वीं पास; मानदेय ₹2,000/माह; 2025-26 लक्ष्य 25,000 के विरुद्ध दिसंबर 2025 तक 25,000 की पहचान
Age 20-45, class-10 pass; ₹2,000/mo; 25,000 identified by Dec 2025 (target 25,000)

लखपति दीदी

Lakhpati Didi: 15 अगस्त 2023; आर्थिक सशक्तिकरण (वार्षिक आय ₹1 लाख); लक्ष्य 20 लाख; 19.90 लाख प्रशिक्षित, 12.98 लाख 'लखपति दीदी' श्रेणी में
15 Aug 2023; ₹1 lakh annual income; target 20 lakh; 19.90 lakh trained, 12.98 lakh became Lakhpati Didi

बैंक सखी / पशु सखी / कृषि सखी (Bank/Pashu/Krishi Sakhi)

बैंक सखी

Bank Sakhi: 7,104 डिजिटल सखी (DG Pay) व 6,053 BC सखी कार्यरत
7,104 DG Pay Sakhis & 6,053 BC Sakhis

पशु/कृषि सखी

Pashu/Krishi Sakhi: पशु सखी (5वीं पास, 4 दिन प्रशिक्षण, ₹1,500/माह) — 37,369; कृषि सखी (56 दिन प्रशिक्षण) — 36,787
Pashu Sakhi (class-5, 4-day training, ₹1,500/mo) — 37,369; Krishi Sakhi (56-day training) — 36,787

4 MGNREGA व रोजगार / MGNREGA & Employment

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGS): अधिनियम 2005; लागू 2 फरवरी 2006; संपूर्ण देश अप्रैल 2008; 2 अक्टूबर 2009 को 'महात्मा गांधी NREGA'। एक वित्त वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी। MGNREGS: Act 2005; in force 2 Feb 2006; pan-India Apr 2008; renamed 'Mahatma Gandhi NREGA' 2 Oct 2009. Guarantees 100 days work/year.
- विशेषताएं: 15 दिन में जॉबकार्ड; 15 दिन में रोजगार न मिले तो बेरोजगारी भत्ता; कार्य 5 किमी परिधि में (अधिक पर 10% अतिरिक्त मजदूरी); महिला 1/3 (राजस्थान में 50%); केंद्र:राज्य (वित्त) 90:10; मजदूरी:सामग्री 60:40। Features: job card in 15 days; allowance if no work in 15 days; work within 5 km (10% extra beyond); women 1/3 (50% in RJ); Centre:State 90:10; wage:material 60:40.
- VB-G RAM G (विकसित भारत — रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण): मनरेगा का उन्नत रूप; 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी; केंद्र:राज्य 60:40 (पहले 10% राज्य के स्थान पर); उत्तर-पूर्वी/हिमालयी हेतु 90:10 यथावत। VB-G RAM G: upgraded MGNREGA; guarantees 125 days; Centre:State 60:40; 90:10 for NE/Himalayan.
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (बजट 2022-23): मनरेगा रोजगार 100→125 दिन; 47 ST ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिन अतिरिक्त; बारां (सहरिया), उदयपुर (कथौड़ी) व विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन अतिरिक्त। MM Rural Employment Guarantee (Budget 2022-23): 100→125 days; +50 days for 47 ST blocks; +100 days for Baran (Sahariya), Udaipur (Kathodi) & disabled workers.

5 अमृत सरोवर व आवास योजनाएं / Amrit Sarovar & Housing Schemes

- मिशन अमृत सरोवर: 24 अप्रैल 2022; राज्य लक्ष्य 2,475 सरोवर; देश के प्रत्येक जिले में 75; प्रति सरोवर 1 एकड़, जल धारण क्षमता 10,000 घन मीटर; प्रथम चरण 3,138 कार्य पूर्ण, दूसरा चरण 601 चिह्नित। Mission Amrit Sarovar: 24 Apr 2022; state target 2,475; 75 per district nationally; each 1 acre, 10,000 cubic m storage; phase-1 3,138 done, phase-2 601 identified.

PM-JANMAN (आवास) (PM-JANMAN (housing))

विवरण

Detail: बजट 2023-24; PVTG (75 जनजातीय समूह); राजस्थान — बारां की 8 पंचायत समिति में सहरिया; ₹2 लाख (आवास) + ₹12,000 (शौचालय) + 90 दिन मनरेगा (~₹25,290)

Budget 2023-24; PVTGs; RJ — Sahariya in 8 panchayat samitis of Baran; ₹2 lakh + ₹12,000 + 90 days MGNREGA

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY (Gramin))

विवरण

Detail: 20 नवंबर 2016; केंद्र:राज्य 60:40; ₹1.20 लाख (आवास) + ₹12,000 (शौचालय, SBM) + 90 दिन रोजगार; SECC-2011 आधार पर चयन
20 Nov 2016; 60:40; ₹1.20 lakh + ₹12,000 + 90 days; SECC-2011 based

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना (Dr SPM District Upliftment (SPMJUY))

विवरण

Detail: जून 2025; जिला-विशिष्ट आवश्यकताएं; सभी जिलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में; ₹500 करोड़ (2025-26)
Jun 2025; district-specific needs; ₹500 cr (2025-26)

पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना (Pt DDU Poverty-Free Village)

विवरण

Detail: 2 जुलाई 2025; BPL जनगणना 2002 के 22 लाख परिवार; 3 चरण (5,000 + 5,000 + 10,000 गाँव); राज्य 100% वित्तपोषित
2 Jul 2025; 22 lakh BPL families; 3 phases (5,000+5,000+10,000 villages); 100% state-funded

6 अवसंरचना विकास योजनाएं / Infrastructure Development Schemes

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD) (MPLAD)

विवरण

Detail: 1993; सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; ₹5 करोड़/वर्ष (गंभीर आपदा ₹1 करोड़); SC 15%, ST 7.5%; केंद्रीय क्षेत्रक योजना; ई-साक्षी पोर्टल
1993; ₹5 cr/yr (₹1 cr for disaster); SC 15%, ST 7.5%; central-sector; e-SAKSHI portal

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLA-LAD) (MLA-LAD)

विवरण

Detail: 1999-2000; ₹5 करोड़/वर्ष; 20% SC/ST, 20% सार्वजनिक उपयोग कार्य
1999-2000; ₹5 cr/yr; 20% SC/ST, 20% public-use

महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना (MG Janbhagidari Vikas (MGJVV))

विवरण

Detail: पुराना नाम गुरु गोलवलकर 2014; फरवरी 2020; राज्य वित्त; अंशदान — श्मशान/कब्रिस्तान 90:10, अन्य 70:30, TSP 80:20, नाम-अंकित 49:51
Formerly Guru Golwalkar 2014; Feb 2020; state-funded; cremation/graveyard 90:10, others 70:30, TSP 80:20, named 49:51

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) (SAGY)

विवरण

Detail: 11 अक्टूबर 2014; प्रत्येक सांसद 1 ग्राम पंचायत/वर्ष; जनसंख्या मैदानी 3,000-5,000, दुर्गम 1,000-3,000; स्वयं या पति-पत्नी का गाँव नहीं
11 Oct 2014; 1 GP/MP/year; plains 3,000-5,000, remote 1,000-3,000; not own/spouse's village

7 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम व बायो फ्यूल / Regional Programmes & Biofuel

- मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: घोषणा 2025-26; अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ/रणनीतिक क्षेत्र; बजट ₹150 करोड़; शिक्षा/स्वास्थ्य/स्वच्छता/पेयजल/कौशल पर केंद्रित। मेवात क्षेत्रीय विकास: 1986-87 से; 3 जिले (अलवर, खैरथल-तिजारा, डींग) के 14 ब्लॉक, 807 गाँव; मेव बहुल; राज्य 100%; बजट 2025-26 ₹100 करोड़। MM Thar Border Area Dev Programme: announced 2025-26; remote/strategic border areas; budget ₹150 cr. Mewat Regional Dev: since 1986-87; 14 blocks, 807 villages of 3 districts; ₹100 cr (2025-26).
- मगरा क्षेत्र विकास: 2005-06 से; 5 जिले (ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़) — मगरा राजस्थान का दक्षिणी-मध्य पहाड़ी भाग। बृज क्षेत्रीय विकास: पूर्वी राजस्थान के 5 जिले (भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डींग, खैरथल-तिजारा)। डांग क्षेत्र विकास: 2005-06 से पुनः; 8 जिले (2,192 गाँव) — डांग बीहड़/घाटीयुक्त दस्यु-ग्रस्त क्षेत्र। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास: अनुसूचित क्षेत्र (TSP)। (इन सभी का बजट 2025-26 ₹100 करोड़; गोविंद गुरु पूर्व में ₹75 करोड़।) Magra Dev: since 2005-06; 5 districts (southern-central hilly). Brij Regional Dev: 5 eastern districts. Dang Area Dev: since 2005-06; 8 districts (2,192 villages; ravine/dacoit-affected). Govind Guru Tribal Regional Dev: TSP. (All ₹100 cr in 2025-26.)
- बायो फ्यूल: मिशन 4 सितंबर 2005; नीति 2006; प्राधिकरण 2007; राजस्थान बायो डीजल नियम 2019; बायो फ्यूल दिवस 10 अगस्त; अध्यक्ष मुख्यमंत्री। राजस्थान जैव ईंधन नियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड: 22 दिसंबर 2016 (पुनर्गठन

11 फरवरी 2022)। Biofuel: Mission 4 Sep 2005; Policy 2006; Authority 2007; RJ Biodiesel Rules 2019; Biofuel Day 10 Aug; chaired by CM. RJ was India's first state to frame biofuel rules. RJ Wasteland & Pasture Dev Board: 22 Dec 2016.

8 पंचायती राज / Panchayati Raj

- पंचायती राज प्रारंभ: नागौर (बगदरी गाँव) से 2 अक्टूबर 1959; संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 (73वां संशोधन); अनुच्छेद 243(G) में शक्तियों का वर्णन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 (1994 में संशोधित), नियम 1996। Panchayati Raj began at Nagaur (Bagdari village) on 2 Oct 1959; constitutional status 24 Apr 1993 (73rd Amendment); powers in Article 243(G). RJ Panchayati Raj Act 1953 (amended 1994), Rules 1996.
- वर्तमान (दिसंबर 2025): 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियाँ व 14,403 ग्राम पंचायत — त्रिस्तरीय व्यवस्था। As of Dec 2025: 41 Zila Parishads, 457 Panchayat Samitis & 14,403 Gram Panchayats — three-tier system.
- मूल कार्य: 73वें संशोधन अनुसार ग्राम-स्तर पर विकेंद्रीकरण; अनुसूचित क्षेत्रों में PESA अधिनियम का क्रियान्वयन; निर्वाचित प्रतिनिधियों (विशेषकर महिला) की क्षमता विकास; ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शिता। Core functions: decentralization (73rd Amendment); PESA in scheduled areas; capacity-building of elected (esp. women) reps; social audit via Gram Sabhas.

9 वित्त आयोग / Finance Commissions

- 16वां वित्त आयोग: अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया; सदस्य — अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष। केंद्र (अनुच्छेद 280) PRI को 41% + 1% (15वें वित्त आयोग अनुसार); टाइड 60%, अनटाइड 40%। 16th Finance Commission: chair Arvind Panagariya; members Ajay Narayan Jha, Annie George Mathew, Manoj Panda, Dr Soumya Kanti Ghosh. PRI gets 41%+1%; tied 60%, untied 40%.
- राज्य वित्त आयोग — अनुच्छेद 243-I (ग्रामीण) व 243(Y) (शहरी)। 7वां राज्य वित्त आयोग: गठन 1 अगस्त 2025; अवधि 1 अप्रैल 2025–31 मार्च 2031; अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी; सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल (सेवानिवृत्त IAS)। State Finance Commission — Art. 243-I (rural) & 243(Y) (urban). 7th SFC: constituted 1 Aug 2025; tenure 1 Apr 2025–31 Mar 2031; chair Dr Arun Chaturvedi.

राजस्थान के राज्य वित्त आयोग

State Finance Commissions of Rajasthan

क्रम #	अध्यक्ष Chairperson	अवधि Tenure
I	कृष्ण कुमार गोयल	1993–2000
II	हीरालाल देवपुरा	2000–2005
III	माणिक चंद सुराणा	2005–2010
IV	B.D. कल्ला	2010–2015
V	ज्योति किरण	2015–2020
VI	प्रद्युम्न सिंह	2020–2025
VII	डॉ. अरुण चतुर्वेदी	2025–2031

- 6वें राज्य वित्त आयोग (ATR): राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 7% हिस्सा वितरित (आधार 2011 जनगणना) — PRI 73.2%, नगरीय निकाय 26.8%; PRI में जिलावार वेटेज — ग्राम पंचायत 75%, पंचायत समिति 20%, जिला परिषद 5%। अनुदान वितरण: 55% आधारभूत/विकास, 40% राष्ट्रीय/राज्य परियोजना, 3% आय-वृद्धि, 2% लिंगानुकूल। 6th SFC (ATR): 7% of net tax revenue shared (2011 census base) — PRI 73.2%, urban 26.8%; within PRI — GP 75%, PS 20%, ZP 5%. Grant split: 55% basic/dev, 40% national/state projects, 3% income-growth, 2% gender-responsive.

10 पंचायती राज योजनाएं व स्वच्छता / Panchayati Raj Schemes & Sanitation

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) (Shri Annapurna Rasoi (Rural))

विवरण

Detail: 6 जनवरी 2024 (पूर्व इंदिरा रसोई 10 सितंबर 2023); राजीविका SHG द्वारा संचालित; 796 रसोई; 600 ग्राम भोजन (चपाती 300g, दाल 100g, सब्जी 100g, चावल/बाजरा खिचड़ी 100g, अचार); शुल्क ₹8/थाली लाभार्थी + ₹22 राज्य

6 Jan 2024 (formerly Indira Rasoi); 796 kitchens; 600g meal; ₹8/plate by beneficiary + ₹22 by state

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (Swachh Bharat Mission (Gramin))

विवरण

Detail: 2 अक्टूबर 2014; जल शक्ति मंत्रालय; 31 मार्च 2018 को राजस्थान ODF घोषित; Phase-2 (2020-21 से) ODF Plus; 4 घटक (व्यक्तिगत शौचालय ₹12,000, सामुदायिक ₹3 लाख/GP, ठोस-तरल अपशिष्ट, गोबर-धन); 2025-26 में 2,205 सामुदायिक परिसर व 1.05 लाख शौचालय

2 Oct 2014; RJ ODF on 31 Mar 2018; Phase-2 ODF Plus; 4 components; 2,205 community complexes & 1.05 lakh toilets in 2025-26

पंचायत पुरस्कार व भवन (Panchayat Awards & Buildings)

पुरस्कार

Awards: 2010-11 से; 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस; दीनदयाल उपाध्याय विशेष श्रेणी व ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार

Since 2010-11; 24 Apr National Panchayat Day; DDU Special & Gram Urja Swaraj awards

भवन

Buildings: ग्राम पंचायत भवन (5 बीघा तक, ₹50 लाख); अंबेडकर भवन योजना (2019-20, सभी पंचायत समिति मुख्यालय, ₹50 लाख/भवन)

GP building (up to 5 bigha, ₹50 lakh); Ambedkar Bhawan (2019-20, ₹50 lakh each)

PDP व स्वामित्व योजना (PDP & SVAMITVA)

PDP

PDP: पंचायत विकास योजना (2015); ग्राम सभा अनुमोदन, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल; जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2025-31 मार्च 2026

Panchayat Development Plan (2015); e-Gram Swaraj portal; Jan Yojana Abhiyan 2 Oct 2025-31 Mar 2026

स्वामित्व

SVAMITVA: 24 अप्रैल 2020 (फ्लैगशिप); पंचायती राज + भारतीय सर्वेक्षण विभाग + राजस्व विभाग; ड्रोन से आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र व पट्टा (राज. पंचायती राज अधिनियम 1996)

24 Apr 2020; Panchayati Raj + SoI + Revenue Dept; drone mapping of abadi & title deeds

11 RUDA, GI-टैग व जल स्वावलंबन / RUDA, GI-Tags & Jal Swavalamban

- RUDA (ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण): स्थापना नवंबर 1995; ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा; GI-टैग दिलाने में सहायता; 3 उपक्षेत्र (चमड़ा, ऊन-वस्त्र, लघु खनिज; कार्यशाला जयपुर में)। RUDA: est. Nov 1995; promotes rural non-farm sector; aids GI-tagging; 3 sub-sectors (leather, wool-textile, minor minerals; workshop at Jaipur).
- राजस्थान में 23 वस्तुओं को GI-टैग प्राप्त — प्रथम बीकानेरी भुजिया; नवीनतम क्रम में सोजत मेहंदी (पाली), पिछवाई कला (नाथद्वारा), जोधपुरी बंधेज, कोफ्तगिरी (उदयपुर), उस्ता कला व कशीदाकारी (बीकानेर), सांगरी व नागौरी अश्वगंधा (23वां)। 23 GI-tagged items in RJ — 1st Bikaneri Bhujia; recent — Sojat Mehndi (Pali), Pichhwai art (Nathdwara), Jodhpuri Bandhej, Koftgiri (Udaipur), Usta art & Kashidakari (Bikaner), Sangri & Nagauri Ashwagandha (23rd).
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (फ्लैगशिप): 18 फरवरी 2024; प्रशासनिक — पंचायती राज, नोडल — जलग्रहण व भू-संरक्षण; 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचना; समिति अध्यक्ष मुख्यमंत्री। अटल ज्ञान केंद्र: 3,000+ जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों पर (ग्रामीण युवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा तैयारी व कैरियर काउंसलिंग)। MM Jal Swavalamban 2.0 (flagship): 18 Feb 2024; admin Panchayati Raj, nodal Watershed; 5 lakh water-harvesting structures in 20,000 villages over 4 yrs; chaired by CM. Atal Gyan Kendra: at 3,000+ population GP HQs.

★ अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs

1. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की स्थापना कब हुई?

RGAVP (Rajeevika) established?

1. अक्टूबर 2010 ✓
2. जून 2011
3. 1 अप्रैल 1999
4. 26 अगस्त 2022

व्याख्या: अक्टूबर 2010 (स्वायत्त परिषद); अध्यक्ष मुख्यमंत्री।
Oct 2010; chaired by CM.

2. NRLM में केंद्र:राज्य वित्त अनुपात क्या है?

NRLM Centre:State funding ratio?

1. 90:10
2. 60:40 ✓
3. 50:50
4. 75:25

व्याख्या: 60:40; जून 2011 से संपूर्ण राज्य में।
60:40; statewide from Jun 2011.

3. राजस्थान महिला कोष की स्थापना कब हुई?

Rajasthan Mahila Kosh established?

1. 26 अगस्त 2022 ✓
2. 15 अगस्त 2023
3. 19 दिसंबर 2021
4. 6 जनवरी 2024

व्याख्या: 26 अगस्त 2022 (महिला समानता दिवस); ब्याज 2.5%, राज्य 8% सब्सिडी।
26 Aug 2022; 2.5% interest, 8% state subsidy.

4. नमो ड्रोन दीदी योजना में कितने SHG को कृषि ड्रोन देने का लक्ष्य है?

Namo Drone Didi — SHG target for drones?

1. 15,000 ✓
2. 1,070
3. 20 लाख
4. 25,000

व्याख्या: 15,000 SHG; वित्त 80% या ₹8 लाख; गढ़ेपान (कोटा) से 11 मार्च 2024।
15,000 SHGs; 80% or ₹8 lakh; from Garhepan (Kota).

5. लखपति दीदी कार्यक्रम में कितनी महिलाएं 'लखपति' श्रेणी में आईं?

Women in 'Lakhpati Didi' category?

1. 19.90 लाख
2. 12.98 लाख ✓
3. 20 लाख
4. 25,000

व्याख्या: 12.98 लाख (19.90 लाख प्रशिक्षित; लक्ष्य 20 लाख)।
12.98 lakh (19.90 lakh trained; target 20 lakh).

6. राज्य में पशु सखी व कृषि सखी की संख्या?

Pashu Sakhi & Krishi Sakhi count?

1. 37,369 व 36,787 ✓
2. 7,104 व 6,053
3. 15,000 व 1,070
4. 517 व 796

व्याख्या: पशु सखी 37,369; कृषि सखी 36,787।

Pashu 37,369; Krishi 36,787.

7. MGNREGA किस तिथि से लागू हुई व इसका नाम कब बदला?

MGNREGA in force & renamed?

1. 2 फरवरी 2006; 2 अक्टूबर 2009 ✓
2. 2005; 2008
3. अप्रैल 2008; 2014
4. 2 अक्टूबर 2009; 2011

व्याख्या: लागू 2 फरवरी 2006; 2 अक्टूबर 2009 को 'महात्मा गांधी NREGA'।

In force 2 Feb 2006; renamed 2 Oct 2009.

8. राजस्थान में मनरेगा के तहत महिला भागीदारी कितनी है?

Women participation in MGNREGA in RJ?

1. 1/3
2. 50% ✓
3. 60%
4. 40%

व्याख्या: राजस्थान में 50% (राष्ट्रीय न्यूनतम 1/3)।

50% in RJ (national minimum 1/3).

9. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना में मनरेगा रोजगार दिवस कितने किए गए?

MGNREGA days under MM Rural Employment?

1. 100
2. 125 ✓
3. 150
4. 50

व्याख्या: 100 से बढ़ाकर 125 दिन; 47 ST ब्लॉकों को 50 दिन अतिरिक्त।

100→125 days; +50 days for 47 ST blocks.

10. मिशन अमृत सरोवर का राज्य लक्ष्य व प्रारंभ तिथि?

Mission Amrit Sarovar target & start?

1. 2,475; 24 अप्रैल 2022 ✓
2. 75; 2014
3. 5,000; 2025
4. 3,138; 2020

व्याख्या: राज्य लक्ष्य 2,475; 24 अप्रैल 2022; प्रति जिला 75; जल धारण 10,000 घन मीटर।

2,475; 24 Apr 2022; 75/district; 10,000 cubic m.

11. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास सहायता कितनी है?

PMAY-Gramin housing aid?

1. ₹2 लाख
2. ₹1.20 लाख ✓
3. ₹50 लाख
4. ₹500 करोड़

व्याख्या: ₹1.20 लाख (आवास) + ₹12,000 (शौचालय) + 90 दिन रोजगार; 20 नवंबर 2016।

₹1.20 lakh + ₹12,000 + 90 days; 20 Nov 2016.

12. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना में कितने BPL परिवार लक्षित हैं?

BPL families targeted in DDU Poverty-Free Village?

1. 12 लाख
2. 22 लाख ✓
3. 20 लाख
4. 500 करोड़

व्याख्या: 22 लाख (BPL जनगणना 2002); 2 जुलाई 2025; राज्य 100% वित्त।
22 lakh (BPL census 2002); 2 Jul 2025.

13. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) में वार्षिक राशि?

MPLAD annual amount?

1. ₹5 करोड़ ✓
2. ₹1 करोड़
3. ₹50 लाख
4. ₹500 करोड़

व्याख्या: ₹5 करोड़/वर्ष; SC 15%, ST 7.5%; गंभीर आपदा ₹1 करोड़।
₹5 cr/yr; SC 15%, ST 7.5%.

14. सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) कब प्रारंभ हुई?

SAGY launch?

1. 11 अक्टूबर 2014 ✓
2. 1993
3. 2018-19
4. 24 अप्रैल 2020

व्याख्या: 11 अक्टूबर 2014; प्रत्येक सांसद 1 ग्राम पंचायत/वर्ष; स्वयं/पति-पत्नी का नहीं।
11 Oct 2014; 1 GP/MP/year.

15. डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है?

Dang Area Development covers how many districts?

1. 5
2. 8 (2,192 गाँव) ✓
3. 3
4. 14

व्याख्या: 8 जिले (2,192 गाँव); डांग = बीहड़/घाटी दस्यु-ग्रस्त क्षेत्र।
8 districts (2,192 villages); ravine area.

16. जैव ईंधन नियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है?

First state to frame biofuel rules?

1. गुजरात
2. राजस्थान ✓
3. महाराष्ट्र
4. कर्नाटक

व्याख्या: राजस्थान (बायो डीजल नियम 2019); बायो फ्यूल मिशन 4 सितंबर 2005।
Rajasthan (Biodiesel Rules 2019).

17. पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ?

Where did Panchayati Raj begin in India?

1. नागौर (बगदरी) ✓
2. जयपुर
3. अजमेर
4. उदयपुर

व्याख्या: नागौर (बगदरी गाँव), 2 अक्टूबर 1959।
Nagaur (Bagdari), 2 Oct 1959.

18. राज्य में (दिसंबर 2025) जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत की संख्या?

Zila Parishads, Panchayat Samitis & GPs (Dec 2025)?

1. 41 / 457 / 14,403 ✓

2. 33 / 295 / 11,000

3. 50 / 500 / 15,000

4. 41 / 352 / 9,894

व्याख्या: 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियाँ, 14,403 ग्राम पंचायत।

41 / 457 / 14,403.

19. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

16th Finance Commission chair?

1. अरविंद पनगढ़िया ✓

2. डॉ. अरुण चतुर्वेदी

3. एन.के. सिंह

4. मनोज पांडा

व्याख्या: अरविंद पनगढ़िया; PRI को 41%+1%।

Arvind Panagariya.

20. 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं व कब गठित हुआ?

7th SFC chair & formation?

1. डॉ. अरुण चतुर्वेदी; 1 अगस्त 2025 ✓

2. प्रद्युम्न सिंह; 2021

3. ज्योति किरण; 2014

4. अरविंद पनगढ़िया; 2025

व्याख्या: डॉ. अरुण चतुर्वेदी; गठन 1 अगस्त 2025; अवधि 2025-2031।

Dr Arun Chaturvedi; 1 Aug 2025; 2025-2031.

21. राजस्थान कब ODF (खुले में शौच मुक्त) घोषित हुआ?

When was RJ declared ODF?

1. 2 अक्टूबर 2014

2. 31 मार्च 2018 ✓

3. 2020-21

4. 24 अप्रैल 2020

व्याख्या: 31 मार्च 2018 (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत)।

31 Mar 2018 (SBM-Gramin).

22. राजस्थान में कितनी वस्तुओं को GI-टैग प्राप्त है?

GI-tagged items in Rajasthan?

1. 23 ✓

2. 17

3. 33

4. 41

व्याख्या: 23 वस्तुएं (प्रथम बीकानेरी भुजिया; 23वां नागौरी अश्वगंधा)।

23 (1st Bikaneri Bhujia; 23rd Nagauri Ashwagandha).